

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 01.05.2024

मू.वि.या. (वाणि.) 337/2021 और अं.आ. 14635/2021,
14862/2022

दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम याचिकाकर्ता
द्वारा: श्री सुरेश त्रिपाठी, सुश्री पूजा दीवान,
श्री उदय सेठ, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स सतिंदर महाजन प्रत्यर्थी
द्वारा: श्री समीर चंदवानी, श्री परवेश सिंह,
अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रतीक जलान

प्रतीक जलान, न्या. (मौखिक)

1. वर्तमान याचिका में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["मध्यस्थता अधिनियम"] के खंड 34 के अधीन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ["एमएसएमई अधिनियम"] के अधीन गठित जिला स्तरीय सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद, पठानकोट ["सुविधा परिषद"] द्वारा पारित मध्यस्थता निर्णय को चुनौती दी गई है।

क. तथ्य

2. प्रत्यर्थी पंजाब के पठानकोट में स्थापित एमएसएमई अधिनियम के अधीन एक मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत है। इसने नई दिल्ली के खरखारी नाहर गांव में एक बस डिपो के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता- दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के साथ दिनांक 21.01.2016 पर एक समझौता ["समझौता"] किया।

3. पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, प्रत्यर्थी ने सुविधा परिषद के समक्ष समझौते के अधीन अपने कथित बकाया के भुगतान के लिए दावा किया। इस उद्देश्य के लिए इसने एमएसएमई अधिनियम के खंड 18 के अधीन सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र को लागू किया। सुविधा परिषद ने सबसे पहले सुलह की कार्यवाही को अपनाया। सुलह की कार्यवाही 15.10.2020 पर बंद कर दी गई थी, और मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया गया था। याचिकाकर्ता ने सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र के बारे में भी आपत्ति जताई, जिसे दिनांक 26.10.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। विवादित पंचाट द्वारा, सुविधा परिषद ने प्रत्यर्थी को रु.4,11,55,845/- (पंचाट की तिथि तक ब्याज सहित) की राशि प्रदान की है। यह निर्विवाद है कि सुविधा परिषद ने अपनी कार्यवाही का संचालन किया, और पठानकोट में अपना पंचाट दिया।

ख. पक्षों की प्रस्तुतियाँ

4. शुरुआत में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री समीर चंदवानी इस याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में आपत्ति उठाते हैं, जो पठानकोट में सुविधा परिषद द्वारा दिए गए मध्यस्थता निर्णय के विरोध में है।

5. श्री चंदवानी प्रस्तुत करते हैं कि एमएसएमई अधिनियम के खंड 18 (4), सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता और भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवादों में मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने आपूर्तिकर्ता होने के नाते पठानकोट, जहां यह स्थित है, में सुविधा परिषद के समक्ष मध्यस्थता का सहारा लिया और पठानकोट मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान था।

6. श्री चांदवानी *श्रेयस विपणन बनाम सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद* में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और *मध्य प्रदेश प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम एमी टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड* में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को यह प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाते हैं कि एमएसएमई अधिनियम के अधीन पारित पंचाट पर उठाई गई चुनौती सुविधा परिषद के स्थान पर होगी।

7. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिपाठी प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के पास मध्यस्थता अधिनियम के खंड 34 के

अधीन याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि दिल्ली के न्यायालय इस समझौते के अधीन विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस उद्देश्य के लिए, वह "सत्यनिष्ठा समझौते" के अनुच्छेद 7 में निहित एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड को आधार बनाते हैं, जो निविदा दस्तावेजों का हिस्सा है। श्री त्रिपाठी के अनुसार, सत्यनिष्ठा समझौता समझौते का हिस्सा है, और उसमें निहित विशेष अधिकार क्षेत्र खंड, समझौते के लिए दिल्ली के न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

8. श्री त्रिपाठी *इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एफ.ई.पी.एल. इंजीनियरिंग (प्रा.) लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पायनियर फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड* में इस न्यायालय के दो खण्ड पीठ के निर्णयों को यह प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाते हैं कि उन मामलों में भी जहाँ एमएसएमई अधिनियम के अधीन कोई भी मध्यस्थता दिल्ली के बाहर स्थित एक सुविधा परिषद द्वारा संचालित की जाती है, पंचाट को चुनौती देने के उद्देश्यों के लिए अधिकार क्षेत्र, विचाराधीन अनुबंध के संदर्भ में विशेष अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में होगा।

9. श्री त्रिपाठी वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत करते हैं कि, भले ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें कोई विशेष अधिकार क्षेत्र खंड नहीं था, वर्तमान मामले में मध्यस्थता का केंद्र दिल्ली है। वह प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थता कार्यवाही में वाद हेतुक पूरी तरह से दिल्ली में उत्पन्न हुआ, और वाद हेतुक का

कोई हिस्सा पठानकोट में उत्पन्न नहीं हुआ। वह बी.बी.आर. (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड बनाम एस.पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस (प्रा.) लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को और भारतीय सीमेंट निगम बनाम एस. सुल्तान में इस न्यायालय के एक समन्वय पीठ का निर्णय को यह तर्क देने के लिए आधार बनाते हैं कि अंतर्निहित विवाद में वाद हेतुक मध्यस्थता के स्थान का निर्धारक है।

ग. विश्लेषण

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं:

क. क्या पक्षों के बीच समझौते में वर्तमान याचिका के लिए कोई विशेष अधिकार क्षेत्र खंड है?

ख. क्या मध्यस्थता का स्थान किसी भी स्थिति में दिल्ली में था?

11. जहाँ तक पहले पहलू का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड [अनुबंध की सामान्य शर्तों ("जीसीसी") का खंड 25] है जिसका शीर्षक "विवादों और मध्यस्थता का निपटान" है। इसमें पक्षों के बीच विवादों के समाधान के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं, और यह उस स्थिति में मध्यस्थता का प्रावधान करता है जहाँ वे अपने विवादों को उसमें प्रदान किए गए तंत्र से हल करने में समर्थ नहीं हैं। जी.सी.सी. में कोई विशेष अधिकार क्षेत्र खंड नहीं है, न ही मध्यस्थता का स्थान निर्धारित किया गया है।

खंड 25, हालांकि, यह प्रावधान करता है कि मध्यस्थता का स्थान "ऐसा स्थान होगा जैसा कि मध्यस्थ द्वारा अपने विवेकानुसार तय किया जा सकता है।

12. श्री त्रिपाठी ने एक स्पष्ट अनन्य अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के संबंध में अपने तर्क \ "सत्यनिष्ठा समझौता" नामक निविदा से जुड़े दस्तावेज के अनुच्छेद 7 (1) पर आधारित किये। सत्यनिष्ठा समझौते पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने थे और इसे निविदा दस्तावेज और पक्षों के बीच समझौते के एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाना था। इसमें कदाचार को रोकने के लिए उपाय करने के लिए बोलीदाता की ओर से कुछ प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, और इसके भंग होने के परिणामों के लिए प्रावधान है।

13. सत्यनिष्ठा समझौते के अनुच्छेद 7 में दो प्रावधान इस विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं:

"अनुच्छेद 7-अन्य प्रावधान

1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल/मालिक के प्रभाग का मुख्यालय है, जिसने निविदा जारी की है।

XXXX

XXXX

XXXX

5) यह स्वीकार्य निबंधन और शर्त है कि इस अखंडता समझौते/समझौते की शर्तों के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद। इस सत्यनिष्ठा समझौते/समझौते या उसकी व्याख्या के अनुसार मालिक/प्रधान द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।"

14. सत्यनिष्ठा समझौते के अनुच्छेद 7 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि इसके संबंध में अधिकार क्षेत्र याचिकाकर्ता होने के नाते मालिक/प्रधान के विभाजन के मुख्यालय के पास है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र या विवादों के समाधान से संबंधित नहीं है। इसलिए यह प्रावधान मुख्य समझौते के अधीन विवादों के लिए अनन्य अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को निर्धारित करने में कम सहायक है। सत्यनिष्ठा समझौते का खंड 7 (5) इस उद्देश्य के लिए अधिक प्रासंगिक है। उक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि सत्यनिष्ठा समझौते के अधीन उत्पन्न होने वाले विवाद और मतभेद और उनकी व्याख्या के प्रश्न मध्यस्थता के अधीन नहीं होंगे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मुख्य समझौते और सत्यनिष्ठा समझौते के अधीन विवाद समाधान तंत्र का उद्देश्य पूरी तरह से अलग होना था; सत्यनिष्ठा समझौते के खंड 7 का उद्देश्य अंतर्निहित समझौते के अधीन उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटना नहीं था। श्री त्रिपाठी द्वारा सुझाए गए दोनों दस्तावेजों को एक साथ पढ़ना होगा, लेकिन इस तरह का पढ़ना सद्भावनापूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। जहाँ तक मुख्य समझौते का संबंध है, संविदात्मक निष्पादन के बारे में विवाद, जो स्वीकार्य रूप से मध्यस्थता कार्यवाही का विषय थे, सत्यनिष्ठा समझौते के खंड 7 में शामिल नहीं हैं।

15. इस प्रकार मैं पाता हूँ कि संविदात्मक शर्तों की उचित व्याख्या पर, पक्षों ने समझौते के अधीन मध्यस्थता के स्थान के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया, और केवल यह प्रावधान किया कि स्थान मध्यस्थ के विवेकानुसार होगा।

16. इस स्तर पर यह उचित होगा कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ के दो निर्णयों से निपटा जाए, जिन को श्री त्रिपाठी ने आधार बनाया है, जिन्होंने एमएसएमई अधिनियम के अधीन मध्यस्थता के संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार किया है। *इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन* में, ठाणे में महाराष्ट्र सुविधा परिषद द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन किया गया था। पक्षों के बीच समझौते में निहित एक विशेष अधिकार क्षेत्र खंड को देखते हुए, जिसे नई दिल्ली में न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के प्रावधान के रूप में पढ़ा गया था, खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। खण्ड पीठ का तर्क निम्नलिखित पैराग्राफ में निहित है:

“20. वर्तमान मामले में, स्थल के साथ-साथ स्थान (अधिकार क्षेत्र खंड के माध्यम से) दोनों नई दिल्ली में होने हैं। इसलिए, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली के न्यायालयों के पास एमएसएमई परिषद द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। चूंकि पक्षकार नई दिल्ली के न्यायालयों को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए सहमत हुए, इस तथ्य के बावजूद कि दिनांक 10 मार्च 2016 के प्रश्नगत खरीद आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा अपने वडोदरा कार्यालय से नवी मुंबई में प्रत्यर्थी को जारी किया गया था, और भले ही दिल्ली में

कोई वाद हेतुक सामने नहीं आया हो, दिल्ली के न्यायालयों के पास मध्यस्थता अधिनियम की खंड 34 के अधीन याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। विशेष रूप से क्योंकि निर्णय के पैरा 19 में उल्लिखित इंडस मोबाइल (उपरोक्त) में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सी.पी.सी. के खंड 16 से 21 को लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस तथ्य के बावजूद कि नई दिल्ली में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि स्थान दिल्ली में होने के लिए सहमती हो गई है, यहाँ के न्यायालयों के पास मध्यस्थता अधिनियम की खंड 34 के अधीन याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

21. एक और पहलू है, जिससे वर्तमान स्तर पर निपटने की आवश्यकता है। एमएसएमई अधिनियम की खंड 18 में प्रावधान है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान पक्षों के बीच विवाद पर लागू होंगे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एमएसएमई की खंड 18 के आधार पर वर्तमान मामले में मध्यस्थता के 'स्थान' का निर्णय किया है और कहा है कि ठाणे में न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

22. एमएसएमई अधिनियम का खंड 18 निम्नानुसार है:

XXXX

XXXX

XXXX

23. निस्संदेह, एमएसएमई अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित एक विशेष कानून है और इसे सामान्य कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी। कई न्यायालयों के निर्णयों में कहा गया है कि एमएसएमई अधिनियम के प्रावधान पक्षों के बीच अनुबंध के प्रावधानों पर अभिभावी रहेंगे। हालाँकि, हम उक्त विवाद में शामिल नहीं हैं और वास्तव में, हमने दलीलों के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को स्पष्ट कर दिया था कि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एमएसएमई परिषद के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों और इसी तरह के अन्य मुद्दों की जांच हमारे द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उन पहलुओं में से किसी पर भी विचार नहीं किया है और आपति याचिका का निर्णय केवल अधिकार क्षेत्र के आधार पर किया है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पक्षों

के बीच सहमत अधिकार क्षेत्र खंड को मंजूरी दी जानी चाहिए।

एम.एस.एम.ई. अधिनियम का प्रधान प्रभाव, इस प्रकार समझा नहीं जा सकता कि पक्षों के बीच हुए समझौते के प्रावधानों को भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस प्रकार, एम.एस.एम.ई. परिषद का अधिकार क्षेत्र जो आपूर्तिकर्ता के स्थान के आधार पर तय किया जाता है, केवल 'स्थल' का निर्धारण करेगा, न कि मध्यस्थता का 'स्थान' का। मध्यस्थता का 'स्थान' पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में शासित होगा, जो वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र खंड संख्या 35 के अनुसार नई दिल्ली है। नतीजतन, इंडस मोबाइल (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, नई दिल्ली के न्यायालयों के पास अधिनियम की खंड 34 के अधीन याचिका पर विचार करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।”

17. इस निर्णय के बाद इरकॉन इंटरनेशनल की खण्ड पीठ ने निर्णय सुनाया है। उक्त मामले में भी, संबंधित एमएसएमई सुविधा परिषद दिल्ली के बाहर स्थित थी, लेकिन पक्षों के बीच समझौते ने दिल्ली में न्यायालयों को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। खण्ड पीठ ने बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचपीसी लिमिटेड, गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम महाकाली फूड्स (प्रा.) लिमिटेड, और शिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल एस.आर.टी.सी. में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के साथ-साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इस न्यायालय के खण्ड पीठ के निर्णयों पर विचार किया। यह गैमन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम सहाय इंडस्ट्रीज में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से सहमत थे और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स (इंडिया)

लिमिटेड बनाम ओजोन अनुसंधान और अनुप्रयोग (आई) (प्रा.) लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया।

18. खण्ड पीठ के उपरोक्त निर्णय उन मामलों में लागू होते हैं जहां पक्ष अपने अनुबंध में किसी विशेष न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही के पर्यवेक्षण के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं। दोनों निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि पक्षों के बीच समझौतों में विशेष अधिकार क्षेत्र खंड, एमएसएमई अधिनियम की धारा 18 के अधीन किसी विशेष एमएसएमई सुविधा परिषद को अधिकार क्षेत्र प्रदान करके अभिभावी नहीं किया जाएगा। ऊपर बताए गए कारणों से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान समझौते में कोई विशेष अधिकार क्षेत्र खंड नहीं है। इसलिए खण्ड पीठ के उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

19. इसके बाद सवाल उठता है कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता का केंद्र पठानकोट है या दिल्ली। श्री त्रिपाठी प्रस्तुत करते हैं कि वाद हेतुक पूर्ण रूप से दिल्ली में उत्पन्न हुआ, क्योंकि कार्य आदेश दिल्ली में जारी किया गया था, समझौते पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, और वास्तव में काम दिल्ली में भी किया गया था। मुझे डर है कि ये दलीलें बहुत प्रासंगिक नहीं हैं, इस सुस्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में निर्धारित किया जाना है, न कि अंतर्निहित विवादों के वाद हेतुक के आधार पर। मध्यस्थता का "स्थान" वह स्थान है जहाँ

मध्यस्थता की कार्यवाही की जाती है; मुकदमा दायर करने के लियर सी.पी.सी. की धारा 16 से 20 के अधीन अधिकार क्षेत्र के निर्धारण की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

20. बी.जी.एस.एस.ओ.एम.ए. में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी सार्थक अन्य निर्देश की अनुपस्थिति में, *"अक्षम्य निष्कर्ष है कि कथित स्थान वास्तव में मध्यस्थ कार्यवाही का न्यायिक स्थान है"*। उपरोक्त दृष्टिकोण का बाद में पालन किया गया है।

21. श्री त्रिपाठी का सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आधार बनाना गलत है, क्योंकि यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अधीन एक निर्णय था, जिसने वाद हेतुक के आधार पर अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की खंड 20 की व्याख्या की थी। बी.बी.आर. (भारत) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसे उन्होंने आधार बनाया था, भी बी.जी.एस. सोमा का अनुसरण करता है। वास्तव में, यह प्रत्यर्थी के मामले का यह अभिनिर्धारित करते हुए समर्थन करता है कि मध्यस्थता अधिनियम के खंड 34 के अधीन याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र केवल सीट न्यायालय के पास है। वाद हेतुक का संदर्भ उस न्यायालय का निर्धारण करने के उद्देश्य से था जिससे कोई पक्ष मध्यस्थता अधिनियम की खंड 9 के अधीन आवेदन के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही की प्रत्याशा में संपर्क कर सकता है। वास्तव में, न्यायालय ने बी.बी.आर. (भारत) में अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता

अधिनियम की खंड 42 उस न्यायालय को अधिकारिता प्रदान नहीं करेगी जिसने खंड 9 के आवेदन पर विचार किया था, यदि वास्तव में मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान मध्यस्थता का स्थान बदल दिया गया था।

22. हालांकि श्रेयस मार्केटिंग में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को एक रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन, श्री चंदवानी ने मुझे निर्णय के पैराग्राफ 7 का एक अवलोकन संदर्भित किया है, कि एमएसएमई अधिनियम की खंड 18 के अधीन पंचाट, जिसे मध्यस्थता अधिनियम के अधीन पंचाट माना जाता है, को संबंधित सुविधा परिषद की पीठ पर उपयुक्त न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह अवलोकन यह निर्धारित करने के संदर्भ में किया गया था कि क्या केरल उच्च न्यायालय रिट याचिका के लिए सुविधाजनक मंच था। हालाँकि, यह प्रत्यर्थी द्वारा बनाए गए मामले का समर्थन करता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एमी टेक इंडिया में केरल उच्च न्यायालय के इस निर्णय का अनुसरण किया है।

23. वर्तमान मामले में, कार्यवाही विशेष रूप से पठानकोट में आयोजित की गई थी और पंचाट वहीं दिया गया था। एक अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के रूप में या अन्यथा, इस बात का कोई अन्य संकेत नहीं है कि मध्यस्थता का स्थान उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर था, जिसे संविदात्मक रूप से भी निर्णय लेने के लिए विद्वान मध्यस्थ पर छोड़ दिया गया था, मुझे सामान्य

सिद्धांत से भिन्न होने का कोई कारण नहीं मिलता है कि मध्यस्थता का स्थान उस स्थान पर था जहां मध्यस्थता आयोजित की गई थी, यानी पठानकोट में।

24. यह एमएसएमई अधिनियम की खंड 18 (4) के उद्देश्य के साथ भी मेल खाता है, जो एक मध्यम या छोटे उद्यम को उस स्थान पर सुविधा परिषद से संपर्क करने की अनुमति देता है जहां वह स्थित है। ऐसे अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड की अनुपस्थिति में जिसके द्वारा ऐसा उद्यम कहीं और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए सहमत होता है, विवाद को उक्त मध्यम या छोटे उद्यम के स्थान पर हल करने के विधायी इरादे को इस व्याख्या द्वारा समर्थन मिलता है।

घ. निष्कर्ष

25. उपरोक्त कारणों से, मेरा मानना है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सभी लंबित आवेदनों के साथ याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन यह आदेश याचिकाकर्ता के विवादित पंचाट को दरकिनार करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष जाने में रुकावट नहीं बनेगा।

26. दिनांक 11.11.2021 के आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि याचिकाकर्ता को तब जारी की जाएगी जब याचिकाकर्ता पंजीकरण को सबूत प्रस्तुत करेगा कि उसने मध्यस्थता अधिनियम की खंड 34 के अधीन किसी अन्य न्यायालय में याचिका दायर की है, ताकि वह उस न्यायालय के

समक्ष उक्त राशि जमा कर सके। यदि आज से तीन महीने के भीतर ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है, तो पक्षकारों को जमा की गई राशि के संबंध में उचित निर्देशों के लिए इन कार्यवाहियों में आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

प्रतीक जलान, न्या.

1 मई, 2024

'भूपि' /टीजे /

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।